रक्षा क्षेत्र में पिछली बार से दोगुनी बढ़ोतरी की जरूरत

नई दिल्ली | मदन जैड़ा

रक्षा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां साल दर साल बजट में बढ़ोतरी की मांग होती है। पिछले दो सालों के दौरान चीन सीमा पर टकराव बढ़ने के कारण सेना के आधुनिकीकरण के कार्य में पहले से ज्यादा तेजी की जरूरत महसूस की गई है।

15
फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश रक्षा मंत्रालय की ओर से की गई है बजट में

सेनाओं के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। इससे आने वाले समय में अतिरिक्त खर्चों को कम किया जा सकेगा लेकिन अभी इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ज्यादा धन की जरूरत है। इसलिए इस बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से बजट में करीब 15 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश की गई है। बजट में इस पर ध्यान दिये जाने की उम्मीद है।

वर्ष 2021-21 का कुल रक्षा बजट 4.78 लाख करोड़ रुपये था जिसमें एक बड़ा हिस्सा 1.16 लाख करोड़ रुपये भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के मद में जाता है। इस प्रकार रक्षा बजट 3.62 लाख करोड़ रुपये रहा। जबकि उससे पहले यह 3.37 लाख करोड़ रुपये था। इसमें 25 हजार करोड़ का इजाफा हुआ था। यानी कुल 7.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। जबकि हाल में रक्षा मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति ने इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताया था। समिति ने कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान महंगाई दर 6.6 फीसदी थी जो पिछले साल के 4.8 फीसदी से ज्यादा है। यदि कुल बजट में महंगाई वृद्धि को समाहित कर लिया जाए तो रक्षा बजट में वास्तविक बढ़ोतरी महज 0.41 फीसदी की हुई। यह स्थिति तब है जब पेंशन के बजट में भी कमी हुई। दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय का तर्क यह था कि सेना के आधुनिकीकरण के बजट में 19 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। जो 1,13,734 से बढ़कर 1,36,060 करोड़ हो गया। सरकार के आंकड़े अपनी जगह हैं लेकिन तीनों सेनाओं की तरफ से यह कहा गया है कि बजट की जितनी जरूरत उनकी तरफ से व्यक्त की गई थी वह नहीं मिला।

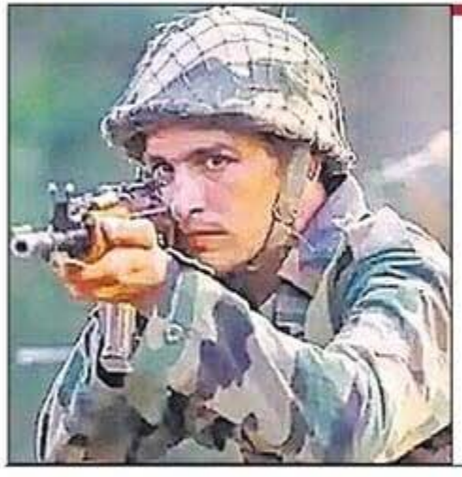

पुराने होते विमान बेड़ों का बोझ

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, जिस प्रकार हाल के वर्षों में भारत की चुनौतियां दोहरे मोर्चे पर बढ़ी हैं और तीनों सेनाओं को बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की जरूरत है, उसके मद्देनजर ज्यादा बजट की जरूरत है। मसलन, विमानों के बेड़े पुराने पड़ रहे हैं। सिर्फ दो स्क्वाड्रन राफेल या कुछ अपाचे हेलीकॉप्टर से जरूरत पूरी नहीं होती है।

सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने से मिलेगा फायदा

सूत्रों के अनुसार, सेनाओं में पुनर्गठन की प्रक्रिया कई स्तरों पर चल रही है जिसका दीर्घकालिक मकसद संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और तात्कालिक खर्च में कटौती लाना है। मसलन, थियेटर कमान बनने से तीनों सेनाओं की संचालनात्मक व्यय में कमी आएगी। इसी प्रकार लाजिस्टिक से जुड़े खर्च में कमी लाने के लिए सेनाओं के भीतर भी अलग से प्रयास चल रहे हैं। एक तिहाई जवानों की सेवानिवृत्ति की उम्र 40 से बढ़ाकर 58 साल करने की तैयारी चल रही है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, पेंशन को छोड़कर शेष रक्षा बजट में करीब 15 फीसदी की बढ़ोतरी की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की गई है।